शनिवार, 13 जून, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

नीरज चोपड़ा की निगाहें अगले अंतरराष्ट्रीय खिताब पर, अभ्यास में जुटे

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि पर बनी दमदार कहानी

Page-05

स्पेसएक्स के लगभग 75 अरब डॉलर के आईपीओ के बाद एलन मस्क की कुल संपत्ति 1 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिससे वे दुनिया के पहले आधिकारिक ट्रिलियनेयर बन सकते हैं। मस्क की अनुमानित 1.1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति ताइवान जैसे विकसित देशों के GDP के बराबर या उससे अधिक बताई जा रही है, जो उनकी अभूतपूर्व आर्थिक शक्ति को दर्शाती है।

स्पेसएक्स IPO के बाद

एलन मस्क बने दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर

दुनिया के सबसे चर्चित उद्यमियों में शुमार एलन मस्क ने वैश्विक आर्थिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी स्पेसएक्स के रिकॉर्डतोड़ आईपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) के बाद मस्क की कुल संपत्ति एक ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार करने की ओर बढ़ गई है, जिसके साथ वह दुनिया के पहले आधिकारिक ट्रिलियनेयर बनने जा रहे हैं। यह उपलब्धि न केवल कारोबारी दुनिया के लिए बल्कि आधुनिक आर्थिक इतिहास के लिए भी अभूतपूर्व मानी जा रही है।स्पेसएक्स लंबे समय से अंतरिक्ष क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली कंपनी के रूप में जानी जाती है। पुन: प्रयोज्य रॉकेट, सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक और अंतरिक्ष अभियानों में कंपनी की सफलताओं ने इसकी बाजार कीमत को लगातार बढ़ाया है। हाल ही में कंपनी के लगभग 75 अरब डॉलर के ऐतिहासिक आईपीओ ने निवेशकों का जबरदस्त ध्यान आकर्षित किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी का मूल्यांकन और अधिक बढ़ सकता है।फोर्ब्स और अन्य वित्तीय विश्लेषकों के अनुमानों के अनुसार, स्पेसएक्स में एलन मस्क की हिस्सेदारी उनकी संपत्ति को 1.1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक तक पहुंचा सकती है। यह राशि कई देशों की कुल अर्थव्यवस्था से भी बड़ी है। तुलना की जाए तो उनकी अनुमानित संपत्ति ताइवान जैसे विकसित अर्थतंत्र के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के बराबर या उससे अधिक बताई जा रही है।एलन मस्क पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला, न्यूरालिंक, एक्सएआई और अन्य तकनीकी कंपनियों के माध्यम से दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में गिने जाते हैं। अब स्पेसएक्स की सफलता ने उनकी आर्थिक ताकत को अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचा दिया है।विशेषज्ञों का कहना है कि मस्क की यह उपलब्धि भविष्य में तकनीक आधारित कंपनियों की भूमिका और निजी क्षेत्र की आर्थिक शक्ति को नए सिरे से परिभाषित कर सकती है। अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में उनके बढ़ते प्रभाव के कारण एलन मस्क केवल एक उद्योगपति नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक और तकनीकी परिदृश्य को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी हस्तियों में शामिल हो चुके हैं।

- स्पेसएक्स के रिकॉर्ड आईपीओ से ऐतिहासिक उपलब्धि
- कई देशों की अर्थव्यवस्था से बड़ी संपत्ति

यूरोप में जयशंकर का करारा जवाब

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की विदेश नीति का मजबूती से बचाव करते हुए पश्चिमी देशों की आलोचनाओं का जवाब दिया है। फिनलैंड में आयोजित कुलतारांता वार्ता के दौरान रूस के साथ भारत के संबंधों और रूसी तेल की खरीद को लेकर पूछे गए सवालों पर जयशंकर ने स्पष्ट और बेबाक रुख अपनाया। उनके बयान को भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता का मजबूत संदेश माना जा रहा है।चर्चा के दौरान जब भारत द्वारा रूस से तेल खरीद जारी रखने पर सवाल उठाए गए, तो जयशंकर ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के आधार पर निर्णय लेता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी देश को भारत के हितों पर प्रश्न उठाने से पहले अपने अतीत और वर्तमान नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए।विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों की कथित दोहरी नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्षों से यूरोप और अन्य देशों द्वारा बेचे गए हथियार भारत के खिलाफ विभिन्न संघर्षों में इस्तेमाल होते रहे हैं। इसके बावजूद भारत को नैतिकता और वैश्विक जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों और रणनीतिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता रहेगा।जयशंकर ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की विदेश नीति किसी दबाव या बाहरी प्रभाव से संचालित नहीं होती। भारत विभिन्न देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाता है। रूस के साथ भारत के संबंध दशकों पुराने हैं और दोनों देशों के बीच ऊर्जा, रक्षा तथा रणनीतिक सहयोग के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी बनी हुई है।

अमेरिका-ईरान युद्धविराम पर बनी सहमति

सप्ताहांत में समझौते पर हस्ताक्षर संभव

मध्य पूर्व में लंबे समय से जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम समझौते को लेकर बड़ी प्रगति सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि दोनों देशों के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता लगभग तय हो चुका है और इस पर इसी सप्ताहांत यूरोप में औपचारिक हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष युद्ध को आगे बढ़ाने के बजाय कूटनीतिक समाधान की दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद क्षेत्र में स्थिरता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकेगा। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि इस अवसर पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस की मौजूदगी संभव है।यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ ही समय पहले अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। अमेरिका द्वारा ईरान के तेल उद्योग को लेकर कड़े बयान दिए गए थे, वहीं सैन्य

कार्रवाई की आशंकाओं ने वैश्विक बाजारों और कूटनीतिक हलकों में चिंता बढ़ा दी थी। हालांकि अब दोनों पक्ष बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह समझौता सफलतापूर्वक लागू हो जाता है तो इससे न केवल अमेरिका और ईरान के संबंधों में सुधार आ सकता है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति और स्थिरता को भी बल मिलेगा। इसके अतिरिक्त वैश्विक तेल बाजारों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार, समझौते में सैन्य गतिविधियों को सीमित करने, क्षेत्रीय तनाव कम करने और संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जैसे बिंदु शामिल हो सकते हैं। हालांकि अंतिम दस्तावेज सार्वजनिक होने के बाद ही इसकी पूरी रूपरेखा स्पष्ट होगी।

दिल्ली के गोविंदपुरी में भीषण अग्निकांड

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी क्षेत्र में शुक्रवार तड़के हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन स्थित एक पांच मंजिला आवासीय इमारत में अचानक आग लगने से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।पुलिस और अग्निशमन विभाग के अनुसार, रात करीब 2:24 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। आग तेजी से इमारत के विभिन्न हिस्सों में फैल गई थी, जिसके कारण अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का पर्याप्त समय नहीं मिल सका।दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि तीन लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। प्रारंभिक जांच में आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट सहित विभिन्न संभावनाओं की जांच की जा रही है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, आग लगने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इमारत से बाहर निकलने का प्रयास किया और आसपास के लोगों ने भी बचाव कार्य में सहयोग किया। घटना के बाद प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।

114 राफेल जेट और तकनीकी हस्तांतरण पर बढ़ी सहमति

भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग एक नए और ऐतिहासिक दौर में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित फ्रांस यात्रा से पहले ऐसी रिपोर्टें सामने आई हैं कि फ्रांस भारतीय वायुसेना के लिए प्रस्तावित 114 राफेल लड़ाकू विमानों की बड़ी परियोजना में व्यापक तकनीकी सहयोग देने को तैयार है। माना जा रहा है कि इस समझौते के तहत केवल विमानों की खरीद ही नहीं, बल्कि उनके निर्माण और उन्नयन से जुड़ी महत्वपूर्ण तकनीकों का हस्तांतरण भी शामिल हो सकता है।भारतीय वायुसेना लंबे समय से अपने लड़ाकू बेड़े के आधुनिकीकरण पर काम कर रही है। मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों और क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ऐसे में 114 राफेल विमानों का प्रस्ताव देश की रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।सूत्रों के अनुसार, फ्रांस अब भारत को केवल रक्षा उपकरणों का खरीदार नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है। इसी सोच के तहत तकनीकी हस्तांतरण, संयुक्त उत्पादन और भारतीय हथियार प्रणालियों के एकीकरण जैसे विषयों पर सकारात्मक चर्चा हो रही है। यदि यह समझौता अंतिम रूप लेता है तो भारत में ही बड़ी संख्या में विमानों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि राफेल विमानों में भारतीय मूल के हथियारों और तकनीकों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। इससे न केवल आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी, बल्कि घरेलू रक्षा उद्योग को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय कंपनियों को अत्याधुनिक एयरोस्पेस तकनीक के क्षेत्र में नई संभावनाएं मिलेंगी।

राज्यसभा चुनाव में 22 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित

राज्यसभा चुनावों की प्रक्रिया के बीच नौ राज्यों से 22 उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन भारतीय राजनीति का प्रमुख घटनाक्रम बनकर सामने आया है। नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कई राज्यों में उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध सीटों के बराबर रही। परिणामस्वरूप इन सीटों पर मतदान की आवश्यकता नहीं रही और सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए।निर्विरोध निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को विशेष लाभ मिला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह स्थिति संबंधित राज्यों में दलों की राजनीतिक ताकत और विपक्षी दलों के बीच सीमित प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है।चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना था, लेकिन जिन राज्यों में उम्मीदवारों की संख्या सीटों के बराबर रही, वहां मतदान की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो गई। अब केवल उन राज्यों में चुनावी मुकाबला होगा जहां उपलब्ध सीटों से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं।राज्यसभा, संसद का उच्च सदन होने के नाते राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहां चुने जाने वाले सदस्य विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कानून निर्माण से लेकर राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा तक में भाग लेते हैं। इसलिए राज्यसभा चुनावों को राजनीतिक दल अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल रखते हैं।विशेषज्ञों के अनुसार, निर्विरोध निर्वाचन कई बार राजनीतिक सहमति का संकेत होता है, जबकि कुछ मामलों में यह विपक्ष की संख्या बल की कमी को भी दर्शाता है। इस बार भी विभिन्न राज्यों में राजनीतिक समीकरणों ने चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया है।

जी-7 शिखर सम्मेलन से पहले कनाडा में कूटनीतिक हलचल तेज

वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा एजेंडे पर दुनिया की नजर

सम्मेलन में रूस-यूक्रेन संघर्ष भी प्रमुख मुद्दा रहेगा। पश्चिमी देश यूक्रेन के समर्थन की अपनी नीति को आगे बढ़ाने के साथ-साथ युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक आर्थिक प्रभावों पर भी विचार करेंगे। खाद्यान्न आपूर्ति, ऊर्जा कीमतों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़े असर को कम करने के लिए सदस्य देशों के बीच साझा रणनीति तैयार की जा सकती है।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

कनाडा में आगामी जी-7 शिखर सम्मेलन को लेकर वैश्विक कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। दुनिया की सात प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं—अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा—के राष्ट्राध्यक्ष एवं शीर्ष नेता इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे समय में जब दुनिया आर्थिक अनिश्चितता, क्षेत्रीय संघर्षों और बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों से गुजर रही है, यह सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है।इस वर्ष सम्मेलन का केंद्र वैश्विक आर्थिक स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे होंगे। हाल के वर्षों में कई देशों को महंगाई, धीमी आर्थिक वृद्धि और व्यापारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में जी-7 देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक निवेश को बढ़ावा देने के उपायों पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।सम्मेलन में रूस-यूक्रेन संघर्ष भी प्रमुख मुद्दा रहेगा। पश्चिमी देश यूक्रेन के समर्थन की अपनी नीति को आगे बढ़ाने के साथ-साथ युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक आर्थिक प्रभावों पर भी विचार करेंगे। खाद्यान्न आपूर्ति, ऊर्जा कीमतों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़े असर को कम करने के लिए सदस्य देशों के बीच साझा रणनीति तैयार की जा सकती है। इसके अलावा युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा भी सम्मेलन के एजेंडे में शामिल है। हाल के महीनों में क्षेत्रीय अस्थिरता ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित किया है। कई देशों ने चिंता जताई है कि यदि प्रमुख समुद्री मार्गों में व्यवधान उत्पन्न होता है तो इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है। ऐसे में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा और वैकल्पिक व्यापारिक व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की जाएगी।विशेषज्ञों का मानना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती तकनीकों का नियमन इस सम्मेलन का एक नया और महत्वपूर्ण विषय होगा। विभिन्न देशों के बीच इस बात पर सहमति बनाने की कोशिश होगी कि नई तकनीकों का उपयोग सुरक्षित, पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से किया जाए। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है।अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों के अनुसार यह सम्मेलन केवल आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में लोकतांत्रिक देशों की भूमिका को भी परिभाषित करेगा। दुनिया की नजरें अब कनाडा में होने वाली इस बैठक पर टिकी हैं, जहां लिए गए फैसले आने वाले समय में वैश्विक राजनीति, व्यापार और सुरक्षा नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं।

दक्षिण कोरिया की नई सरकार के सामने विदेश नीति की चुनौती, क्षेत्रीय सुरक्षा पर रहेगा फोकस

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

चुनौती क्षेत्रीय सुरक्षा, उत्तर कोरिया के साथ संबंधों और प्रमुख वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने की है। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद नई नेतृत्व टीम ने संकेत दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग उसकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेंगे।पूर्वी एशिया में बदलते रणनीतिक समीकरणों के बीच दक्षिण कोरिया की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों को लेकर पहले से ही सुरक्षा संबंधी चिंताएं बनी हुई हैं। ऐसे में नई सरकार को सुरक्षा नीति और कूटनीतिक पहल के बीच संतुलन स्थापित करना होगा।सरकार ने अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की इच्छा जताई है। इसके साथ ही जापान और अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच दक्षिण कोरिया की विदेश नीति आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। वैश्विक व्यापार में उतार-चढ़ाव और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के दौर में दक्षिण कोरिया अपनी निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहा है। नई सरकार तकनीकी नवाचार, निवेश और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने की रणनीति पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।

भारत ने फिर से अमेरिका के शीर्ष राजनयिक को तलब किया

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

ओमान के तट पर कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स जेसन मीक्स को तलब किया। कल, 20 भारतीय क्रू सदस्यों वाले एक और जहाज पर हमला हुआ। विदेश मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी (अमेरिका) ने अमेरिकी राजनयिक को बुलाया था। यह दूसरी बार है जब विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी मिशन को तलब किया है। हमलों में से एक में तीन भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनके बारे में शुरू में लापता होने की खबर थी। बता दें कि पिछले कुछ ही दिनों में यह दूसरी बार है जब भारत ने किसी अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है। विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (अमेरिका) नागराज नायडू ने जेसन मीक्स को इस मामले में तलब किया। इसे लेकर बैठक लगभग 40 मिनट तक चली, जिसमें भारत ने कॉमर्शियल जहाज पर हुए हमले और उसमें तीन भारतीयों के मारे जाने पर अपना कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। कहा जा रहा है कि भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर फिलहाल दिल्ली से बाहर हैं, इसलिए उनकी जगह जेसन मीक्स को यह कूटनीतिक विरोध सौंपने के लिए बुलाया गया है और उन्हें जवाब देना होगा। मुख्य रूप से तीन कॉमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों से जुड़े मामले में भारत ने सख्त रुख अपना है। अमेरिकी सेना ने ये हमला उस जहाज पर किया जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय चालक दल मौजूद थे। इससे पहले बुधवार को ओमान के सोहर बंदरगाह के पास पलाऊ-झंडे वाले टैंकर को अमेरिका ने निशाना बनाया था। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी सेना द्वारा दागी गई मिसाइल के कारण जहाज के इंजन रूम में आग लग गई और इस हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। इस हमले से पहले सोमवार को अमेरिकी नौसेना ने एक अन्य भारतीय जहाज पर हमला किया था, जिसपर 24 भारतीय नाविक मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया था।

नेपाल में सत्ता समीकरणों को लेकर बढ़ी हलचल राजनीतिक दलों के बीच मंथन जारी

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

नेपाल की राजनीति में एक बार फिर गठबंधन और सत्ता संतुलन को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। देश के प्रमुख राजनीतिक दल वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और भविष्य की रणनीतियों को लेकर लगातार बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। हालिया घटनाक्रमों ने यह संकेत दिया है कि विभिन्न दल अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयारी में जुटे हैं।राजनीतिक सूत्रों के अनुसार सत्ता पक्ष और सहयोगी दलों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श जारी है। आर्थिक सुधार, विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। सरकार की प्राथमिकता विकास योजनाओं को गति देने और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने पर केंद्रित बताई जा रही है।नेपाल की राजनीति में गठबंधन सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में दलों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखना किसी भी सरकार की सफलता के लिए आवश्यक माना जाता है। हाल के दिनों में विभिन्न नेताओं के बयानों और बैठकों ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। हालांकि प्रमुख दलों ने राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है।विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल की आंतरिक राजनीति का असर क्षेत्रीय कूटनीति पर भी पड़ता है। भारत और चीन जैसे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को संतुलित बनाए रखना नेपाल की विदेश नीति की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसलिए देश के राजनीतिक घटनाक्रमों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नजर रखी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले सप्ताह नेपाल की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यदि दलों के बीच सहमति और समन्वय बना रहता है तो सरकार को अपनी विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। फिलहाल देश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं और सभी की निगाहें प्रमुख दलों के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।

लॉस एंजिलिस में आव्रजन नीति के खिलाफ प्रदर्शन तेज, राष्ट्रीय राजनीति में छिड़ी नई बहस

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजिलिस शहर में आव्रजन नीति को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। हाल के दिनों में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रशासन की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नई नीतियां प्रवासी समुदायों के अधिकारों और हितों को प्रभावित कर रही हैं, जबकि सरकार का कहना है कि उसके कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उठाए गए हैं।प्रदर्शनों के दौरान शहर के कई प्रमुख इलाकों में रैलियां, मार्च और जनसभाएं आयोजित की गईं। स्थानीय प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति भी देखने को मिली, हालांकि अधिकांश कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए।आव्रजन का मुद्दा लंबे समय से अमेरिकी राजनीति का एक संवेदनशील विषय रहा है। देश में लाखों प्रवासी समुदायों की मौजूदगी के कारण इस विषय का सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। मानवाधिकार संगठनों और नागरिक समूहों ने

सरकार से अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की मांग की है। उनका कहना है कि कई परिवार और श्रमिक समुदाय इन नीतियों से प्रभावित हो सकते हैं।दूसरी ओर प्रशासन का तर्क है कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करना और अवैध आव्रजन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सरकार का कहना है कि देश की सुरक्षा और संसाधनों के संतुलित उपयोग के लिए प्रभावी आव्रजन व्यवस्था जरूरी है। इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच भी तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिल रही है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावी माहौल में आव्रजन का मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। यह विषय न केवल प्रवासी समुदायों बल्कि व्यापक अमेरिकी मतदाता वर्ग को भी प्रभावित करता है। फिलहाल लॉस एंजिलिस में जारी विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बने हुए हैं और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है।

संपादक की कलम से

भारत आज दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में शामिल है। यह जनसांख्यिकीय शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक कौशल और पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं तो यही युवा शक्ति भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। लेकिन यदि यह क्षमता सही दिशा नहीं पाती, तो यह सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का कारण भी बन सकती है।

हाल ही में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक में रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया। यह स्वागतयोग्य पहल है क्योंकि आज देश के सामने सबसे बड़ी जरूरत केवल रोजगार उपलब्ध कराने की नहीं, बल्कि ऐसे रोजगार सृजित करने की है जो बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था की मांगों के अनुरूप हों। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा और डिजिटल तकनीकों के बढ़ते प्रभाव के बीच पारंपरिक कौशल पर्याप्त नहीं रह गए हैं।

भारत में हर वर्ष लाखों युवा रोजगार बाजार में प्रवेश करते हैं। ऐसे में केवल सरकारी नौकरियों पर निर्भर रहना व्यावहारिक समाधान नहीं हो सकता। आवश्यकता इस बात की है कि निजी क्षेत्र, स्टार्टअप, लघु एवं मध्यम उद्योग तथा उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जाए। साथ ही कौशल विकास कार्यक्रमों को स्थानीय उद्योगों और बाजार की जरूरतों से जोड़ा जाए ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को वास्तविक रोजगार मिल सके।

राज्यों की भूमिका भी इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक राज्य की आर्थिक संरचना, संसाधन और आवश्यकताएं अलग हैं। इसलिए रोजगार और कौशल विकास की योजनाओं में राज्यों को अधिक लचीलापन और संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित प्रयास ही इस लक्ष्य को सफल बना सकते हैं।

इसके साथ ही शिक्षा प्रणाली में भी सुधार आवश्यक है। विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल डिग्री आधारित शिक्षा के बजाय कौशल आधारित प्रशिक्षण, तकनीकी दक्षता और नवाचार को बढ़ावा देना होगा। युवाओं को रोजगार खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाला बनाने की दिशा में भी प्रयास बढ़ाने होंगे।

विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब देश का युवा आत्मनिर्भर, कुशल और आर्थिक रूप से सशक्त बने। रोजगार और कौशल विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि भारत के भविष्य में निवेश है। यही निवेश आने वाले वर्षों में देश की प्रगति की सबसे मजबूत नींव साबित होगा।

पंजाब कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की तैयारी चुनावी रणनीति को धार देने में जुटा हाईकमान

कांग्रेस नेतृत्व यह भी चाहता है कि आगामी चुनावों से पहले पार्टी के भीतर मौजूद मतभेदों को कम किया जाए और सभी नेताओं को एक मंच पर लाया जाए। माना जा रहा है कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर संगठन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सकते हैं। इसमें प्रदेश स्तर से लेकर जिला इकाइयों तक जिम्मेदारियों में फेरबदल की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच कांग्रेस नेतृत्व ने राज्य संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पार्टी हाईकमान ने पंजाब कांग्रेस की स्थिति का आकलन करने और संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय पर्यवेक्षक समिति नियुक्त की है। इस समिति में वरिष्ठ नेता अजय माकन, मीनाक्षी नटराजन और भजनलाल जाटव को शामिल किया गया है। समिति का उद्देश्य राज्य इकाई में मौजूद चुनौतियों का अध्ययन कर पार्टी नेतृत्व को विस्तृत रिपोर्ट सौंपना है।पिछले कुछ वर्षों में पंजाब कांग्रेस लगातार आंतरिक गुटबाजी, नेतृत्व विवाद और संगठनात्मक असंतुलन जैसी समस्याओं से जूझती रही है। विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने और जनता के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की रही है। ऐसे में हाईकमान का यह कदम आगामी चुनावों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।सूत्रों के अनुसार पर्यवेक्षक समिति विभिन्न जिलों का दौरा कर स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत करेगी। इसके साथ ही संगठन की मजबूती, बूथ स्तर पर सक्रियता, जनसंपर्क अभियानों और चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। समिति यह भी जांचेगी कि किन क्षेत्रों में पार्टी को सबसे अधिक सुधार की आवश्यकता है और किस प्रकार संगठन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंजाब कांग्रेस के सामने केवल संगठनात्मक चुनौतियां ही नहीं हैं, बल्कि उसे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक ताकतों से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व राज्य में नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पार्टी का प्रयास है कि वरिष्ठ नेताओं और युवा कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर एक मजबूत चुनावी ढांचा तैयार किया जाए।कांग्रेस नेतृत्व यह भी चाहता है कि आगामी चुनावों से पहले पार्टी के भीतर मौजूद मतभेदों को कम किया जाए और सभी नेताओं को एक मंच पर लाया जाए। माना जा रहा है कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर संगठन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सकते हैं। इसमें प्रदेश स्तर से लेकर जिला इकाइयों तक जिम्मेदारियों में फेरबदल की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है।राजनीतिक जानकारों के अनुसार पंजाब कांग्रेस के लिए आने वाले कुछ महीने बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यदि पार्टी संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में सफल रहती है, तो वह राज्य की राजनीति में अपनी स्थिति को पहले से अधिक मजबूत बना सकती है। हाईकमान की ताजा पहल को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। पार्टी का कहना है कि युवाओं और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है, जिसके कारण लोगों में असंतोष बढ़ रहा है।कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि रोजगार के अवसर सीमित होते जा रहे हैं जबकि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं। कई राज्यों में भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। पार्टी का कहना है कि इन मामलों में जवाबदेही तय करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है।महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने दावा किया कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से आम परिवारों का बजट प्रभावित हुआ है। पार्टी नेताओं का कहना है कि रसोई गैस, खाद्य सामग्री और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों की परेशानियां बढ़ा दी हैं।कांग्रेस ने घोषणा की है कि आंदोलन के तहत जिला मुख्यालयों, राज्य राजधानियों और प्रमुख शहरों में प्रदर्शन, जनसभाएं और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुख राजनीतिक एजेंडा बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े सवालों के जरिए वह जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर सकेगी।

टीएमसी में बढ़ी अंदरूनी असहमति सांसदों की मांग से सियासत गरमाई

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय नया राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया जब तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कई सांसदों द्वारा लोकसभा में अलग बैठने की मांग को लेकर असहमति के स्वर उभरने की खबरें सामने आईं। इस घटनाक्रम ने पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी चर्चाओं और असंतोष को लेकर अटकलों का दौर तेज कर दिया है।सूत्रों के अनुसार कुछ सांसदों ने पार्टी नेतृत्व के समक्ष संगठनात्मक और संसदीय कार्यप्रणाली से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। हालांकि पार्टी की ओर से किसी बड़े मतभेद से इनकार किया गया है, लेकिन विपक्षी दल इस घटनाक्रम को टीएमसी के भीतर बढ़ती असहमति का संकेत बता रहे हैं।राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि लोकसभा चुनावों और उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए समीकरण पैदा किए हैं। ऐसे में विभिन्न दल अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और भविष्य की रणनीति तय करने में जुटे हुए हैं।टीएमसी नेतृत्व ने पार्टी के सभी सांसदों और नेताओं से एकजुटता बनाए रखने की अपील की है। पार्टी का कहना है कि लोकतांत्रिक संगठन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होना स्वाभाविक है और इसे किसी बड़े संकट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि पार्टी के भीतर असंतोष लगातार बढ़ रहा है और इसका असर भविष्य की राजनीतिक रणनीतियों पर पड़ सकता है।राजनीतिक जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में यदि पार्टी नेतृत्व स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने में सफल रहता है तो विवाद जल्द शांत हो सकता है। फिलहाल यह घटनाक्रम पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है और सभी की नजरें टीएमसी नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।

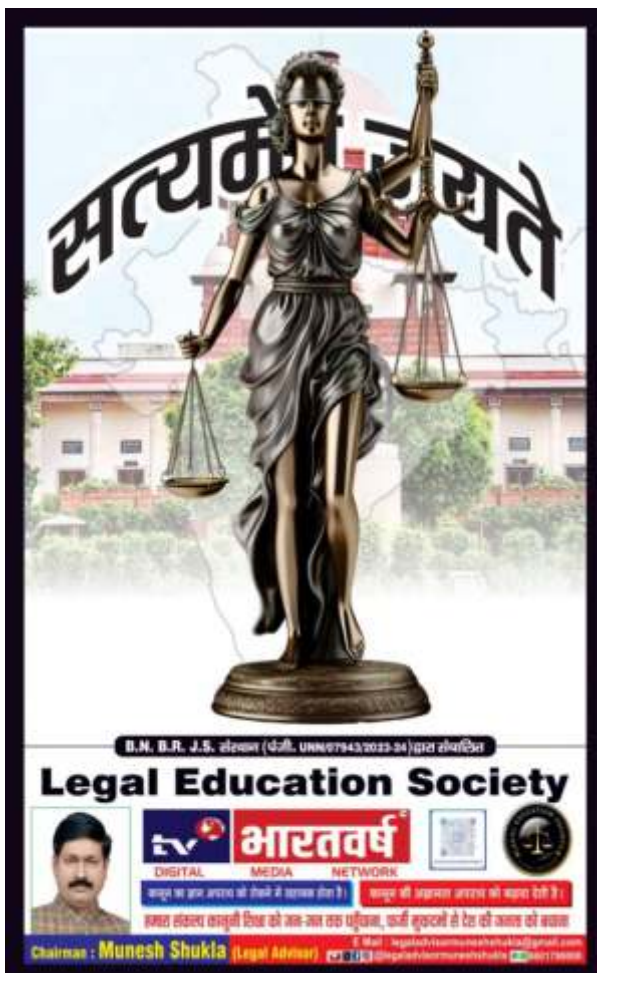

पीएचडी के दौरान कमाई भी, पढ़ाई भी

जानिए सरकार की प्रमुख फेलोशिप योजनाएं

देश में हायर एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और विभिन्न सरकारी संस्थाएं पीएचडी (PhD) करने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप और फेलोशिप योजनाएं उपलब्ध कराती हैं. इन योजनाओं के तहत शोधार्थियों को हर महीने 37,000 से लेकर 1 लाख रुपये या उससे अधिक तक की आर्थिक सहायता दी जाती है. साथ ही कई योजनाओं में रिसर्च ग्रांट और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं. प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप (PMRF) मुख्य रूप से IIT, IISc, IISER और अन्य शीर्ष संस्थानों में पीएचडी करने वाले छात्रों के लिए है. इस योजना के तहत शोधार्थियों को पहले दो वर्षों के लिए 70,000 प्रति माह, तीसरे वर्ष 75,000 और चौथे एवं पांचवें वर्ष 80,000 प्रति माह तक की फेलोशिप मिलती है. इसके अलावा पांच वर्षों में कुल 10 लाख तक का रिसर्च ग्रांट भी दिया जाता है. देश में पीएचडी फंडिंग का सबसे लोकप्रिय माध्यम UGC-NET और CSIR-NET जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) है. यह फेलोशिप विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और अन्य विषयों के छात्रों को दी जाती है. NET-JRF क्वालिफाई करने वाले छात्रों को शोध कार्य के दौरान मासिक स्टाइपेंड दिया जाता है. फेलोशिप की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष तक होती है, जिसमें प्रारंभिक वर्षों में JRF और बाद में SRF (सीनियर रिसर्च फेलोशिप) का लाभ मिलता है. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) तरह से चलाई जा रही INSPIRE Fellowship उन छात्रों के लिए है जिन्होंने विज्ञान विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और रिसर्च के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं.यह फेलोशिप बेसिक और एप्लाइड साइंस के शोधार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है. इसका उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को वैज्ञानिक अनुसंधान की ओर आकर्षित करना है. इंजीनियरिंग और तकनीकी विषयों में पीएचडी करने वाले छात्रों के लिए AICTE Doctoral Fellowship (ADF) एक जरूरी योजना है. इस योजना के तहत चयनित शोधार्थियों को 37,000 से 42,000 प्रतिमाह तक की फेलोशिप प्रदान की जाती है. यह योजना पूर्णकालिक पीएचडी छात्रों को शोध के दौरान आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराती है ताकि वे बेहतर तरीके से अपना अध्ययन और अनुसंधान पूरा कर सकें. अगर कोई शोधार्थी उद्योगों से जुड़े विषयों पर रिसर्च करना चाहता है, तो प्रधानमंत्री फेलोशिप फॉर डॉक्टोरल रिसर्च उसके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है. यह योजना सरकार और निजी उद्योगों की साझेदारी पर आधारित है. इसके तहत शोधार्थियों को JRF और SRF की तुलना में कहीं अधिक वित्तीय सहायता मिल सकती है. कई मामलों में फेलोशिप राशि 1 लाख रुपये प्रति माह तक पहुंच जाती है. सरकार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों के लिए भी विशेष राष्ट्रीय फेलोशिप योजनाएं संचालित करती है. इन योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा और शोध के लिए प्रोत्साहित करना है. इसके अलावा UGC पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप फॉर वूमेन जैसी योजनाएं भी उपलब्ध हैं, जिनका लाभ पीएचडी पूरी कर चुकी महिलाएं उठा सकती हैं. यह योजना महिला शोधकर्ताओं को उच्च स्तर के अनुसंधान कार्य जारी रखने में सहायता प्रदान करती है.

NTA ने NEET UG 2026 परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने NEET UG 2026 परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है. 21 जून 2026 को होने वाली NEET UG परीक्षा में छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ अहम बदलाव किए गए हैं. NTA ने परीक्षा की कुल अवधि बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है, जिससे उम्मीदवारों को पेपर हल करने के लिए बेहतर समय मिल सकेगा. इसके साथ ही प्रश्न पत्र में रफ वर्क करने के लिए भी ज्यादा जगह उपलब्ध कराई जाएगी. NTA के अनुसार ये बदलाव छात्रों से मिले फीडबैक और परीक्षा प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं. NTA ने बताया है कि NEET UG 2026 परीक्षा की अवधि अब 195 मिनट कर दी गई है. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी. इसमें अटेंडेंस शीट पर साइन करने और परीक्षा से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाओं का समय भी शामिल रहेगा. NTA का कहना है कि यह बदलाव उम्मीदवारों से मिले फीडबैक के आधार पर किया गया है. इसका उद्देश्य यह है कि छात्रों को पेपर हल करने के लिए पर्याप्त समय मिले और प्रशासनिक प्रक्रिया की वजह से उनका परीक्षा समय प्रभावित न हो. NEET UG 2026 के प्रश्न पत्र में रफ वर्क के लिए भी बदलाव किया गया है. अब उम्मीदवारों को रफ काम, कैलकुलेशन और डायग्राम बनाने के लिए पहले से ज्यादा जगह उपलब्ध कराई जाएगी.पहले रफ वर्क के पेज केवल प्रश्न पत्र के अंत में दिए जाते थे. अब प्रश्न पत्र की शुरुआत में भी रफ वर्क के लिए पेज उपलब्ध होंगे. इससे छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार काम करने में मदद मिलेगी. NTA ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड और इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और परीक्षा केंद्र पर नियमों का पालन करें. एजेंसी के अनुसार ये बदलाव परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा सुविधाजनक और उम्मीदवारों के अनुकूल बनाने के लिए किए गए हैं.

प्रो कबड्डी लीग के नए सत्र की तैयारियां शुरू फ्रेंचाइजियों ने बनाई रणनीति

भारत-इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला से पहले टीम संयोजन पर मंथन युवा खिलाड़ियों पर नजर

भारत और इंग्लैंड के बीच आगामी टेस्ट श्रृंखला को लेकर क्रिकेट जगत में उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रृंखला शुरू होने से पहले भारतीय टीम प्रबंधन अंतिम संयोजन तय करने में जुटा हुआ है। अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ युवा प्रतिभाओं को भी अवसर दिए जाने की संभावना ने चयन प्रक्रिया को और रोचक बना दिया है। यह श्रृंखला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के नए चक्र के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती विदेशी परिस्थितियों में संतुलित और मजबूत संयोजन तैयार करना है। टीम प्रबंधन बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में सही संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन के आधार पर कई युवा खिलाड़ियों ने चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यही कारण है कि अंतिम एकादश को लेकर लगातार चर्चा हो रही है।कोचिंग स्टाफ का मानना है कि इंग्लैंड की परिस्थितियों में तेज गेंदबाजों की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। वहीं बल्लेबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट के खिलाफ धैर्यपूर्ण प्रदर्शन करना होगा। अभ्यास सत्रों में खिलाड़ियों का विशेष ध्यान तकनीकी तैयारी और परिस्थितियों के अनुरूप रणनीति पर केंद्रित है।भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की नजरें विशेष रूप से युवा खिलाड़ियों पर टिकी हुई हैं। पिछले कुछ वर्षों में घरेलू क्रिकेट और आईपीएल से उभरे कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह मजबूत करने का दावा पेश किया है। चयनकर्ताओं के सामने चुनौती यह है कि अनुभव और युवा ऊर्जा के बीच सही संतुलन स्थापित किया जाए।

फीफा क्लब विश्व कप को लेकर बढ़ा उत्साह दुनिया के शीर्ष क्लबों की तैयारी पूरी

फुटबॉल जगत की सबसे प्रतिष्ठित क्लब प्रतियोगिताओं में शामिल फीफा क्लब विश्व कप को लेकर दुनिया भर में उत्साह बढ़ता जा रहा है। इस बार टूर्नामेंट को विशेष महत्व दिया जा रहा है क्योंकि इसमें विभिन्न महाद्वीपों के चैंपियन क्लब एक ही मंच पर अपनी ताकत दिखाते नजर आएंगे। यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के प्रमुख क्लबों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।फुटबॉल विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रतियोगिता में यूरोपीय क्लबों को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। हालांकि दक्षिण अमेरिकी और एशियाई क्लब भी हाल के वर्षों में अपने प्रदर्शन से यह साबित कर चुके हैं कि वे किसी भी बड़े प्रतिद्वंद्वी को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। इसी कारण इस बार प्रतियोगिता में कई रोमांचक मुकाबलों की उम्मीद की जा रही है।टीमों के प्रशिक्षण शिविरों में खिलाड़ियों की फिटनेस, रणनीति और तकनीकी कौशल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोच अपने खिलाड़ियों को विभिन्न परिस्थितियों के लिए तैयार करने में जुटे हैं। कई क्लबों ने नए खिलाड़ियों को शामिल कर अपनी टीमों को और मजबूत बनाया है। इसके अलावा चोटिल खिलाड़ियों की वापसी भी कई टीमों के लिए राहत की खबर है। फुटबॉल प्रशंसकों के लिए यह टूर्नामेंट दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को एक साथ देखने का अवसर प्रदान करेगा। कई दिग्गज खिलाड़ी अपने क्लबों के लिए खिताब जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेंगे। सोशल मीडिया और खेल जगत में टूर्नामेंट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और टिकटों की मांग भी बढ़ रही है। विश्लेषकों के अनुसार क्लब विश्व कप केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि वैश्विक फुटबॉल की ताकत और लोकप्रियता का प्रतीक बन चुका है। प्रतियोगिता के परिणामों का असर क्लबों की प्रतिष्ठा और भविष्य की योजनाओं पर भी पड़ता है। ऐसे में सभी टीमों के बीच खिताब जीतने की होड़ बेहद दिलचस्प रहने वाली है।

नीरज चोपड़ा की निगाहें अगले अंतरराष्ट्रीय खिताब पर अभ्यास में जुटे ओलंपिक चैंपियन

भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी में पूरी मेहनत के साथ जुटे हुए हैं। विश्व एथलेटिक्स में अपनी अलग पहचान बना चुके नीरज की नजर अब आने वाले बड़े आयोजनों में शानदार प्रदर्शन करने और एक और अंतरराष्ट्रीय खिताब अपने नाम करने पर है।हाल के वर्षों में नीरज चोपड़ा ने भारतीय खेल जगत को कई ऐतिहासिक उपलब्धियां दिलाई हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद उन्होंने विश्व चैंपियनशिप और डायमंड लीग जैसे बड़े मंचों पर भी लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। उनकी सफलता ने न केवल भारतीय एथलेटिक्स को नई पहचान दी है बल्कि लाखों युवाओं को भी खेलों के प्रति प्रेरित किया है।सूत्रों के अनुसार नीरज इन दिनों अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उनकी कोचिंग टीम तकनीकी सुधार, शारीरिक क्षमता और फिटनेस को और बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन बनाए रखना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी चुनौती होता है और नीरज भी इसी लक्ष्य के साथ अभ्यास कर रहे हैं।खेल विशेषज्ञों का मानना है कि नीरज के पास अनुभव और आत्मविश्वास दोनों मौजूद हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रतिद्वंद्वी भी मजबूत हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नीरज ने दबाव में शानदार प्रदर्शन कर अपनी क्षमता साबित की है। भारतीय खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि वे आगामी प्रतियोगिताओं में भी देश का नाम रोशन करेंगे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ भी नीरज की तैयारियों पर नजर बनाए हुए है। आने वाले महीनों में कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं आयोजित होने वाली हैं, जिनमें उनका प्रदर्शन भारतीय खेल जगत के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल नीरज पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं।

गलती की सजा नौकरी से निकालना कहां तक सही?

'370 वसूल करूंगा' विवाद में नई बहस

370 रुपये की बिरयानी को लेकर वायरल हुए हिमांशु जांगड़ा का मामला अब सिर्फ एक विवादित टिप्पणी तक सीमित नहीं रह गया है. उनकी नौकरी जाने के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है. सवाल उठ रहे हैं कि किसी गलत बयान की सजा की सीमा क्या होनी चाहिए. क्या सार्वजनिक आलोचना के बाद नौकरी छिन जाना उचित माना जा सकता है? पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कॉमेडियन प्रनीत मोरे के एक क्राउडवर्क शो में हिमांशु जांगड़ा ने अपनी डेट से जुड़ा किस्सा शेयर किया. वायरल क्लिप में उन्होंने कहा कि उन्होंने एक महिला के लिए 370 रुपये की बिरयानी खरीदी थी और इसलिए वह 'पैसा वसूल' करना चाहते थे. उनकी

एक कमेंट को सोशल मीडिया पर कई लोगों ने महिलाओं के प्रति अपमानजनक और अधिकार जताने वाली सोच का उदाहरण बताया. वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर तीखी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसी सोच रिश्तों और सहमति की बुनियादी समझ पर सवाल खड़े करती है. विवाद और बढ़ गया जब कुछ लोगों ने हिमांशु के कथित पुराने सोशल मीडिया पोस्ट भी शेयर किए. एक यूजर ने लिखा-जो लोग उसके लिए सहानुभूति जता रहे हैं, उन्हें उसकी सोच भी देखनी चाहिए. हालांकि, मामले ने जल्द ही एक अलग मोड़ ले लिया. बड़ी संख्या में लोग यह कहने लगे कि टिप्पणी चाहे कितनी भी गलत क्यों न हो, नौकरी खोना बहुत बड़ी सजा है. एक वायरल पोस्ट में लिखा गया-उसने जो कहा वह गलत था, उसकी सोच भी गलत है, लेकिन किसी की नौकरी चले जाना बेहद गंभीर बात है. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या किसी व्यक्ति के निजी विचारों या सार्वजनिक मंच पर कही गई बातों का असर उसके पेशेवर जीवन पर पड़ना चाहिए.

बच्ची की बात सुनकर रो पड़े लोग

'सबके पापा हैं, आप दारू पीकर मर गए'

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसे देख लोगों की आंखें नम हो रही है. वीडियो में एक छोटी बच्ची अपने दिवंगत (मरे हुए) पिता की तस्वीर के सामने खड़ी होकर उनसे ऐसे सवाल पूछती है, जिनका जवाब अब शायद कभी नहीं मिल सकता. उसकी मासूम बातें सुनकर हर किसी का दिल भर आ रहा है. इस पोस्ट पर 3.5 मिलियन व्यूज हैं और इस पर 5 हजार से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया है. बच्ची तस्वीर को देखते हुए कहती है- मम्मी मना करती थी न दारू पीने, आप नहीं माने... सबके पापा हैं, आप दारू पीकर मर गए.

अमेरिका में भारतीय शख्स की कमाई सुन लोग हैरान

अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय टेक प्रोफेशनल का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में जब उसने अपनी सालाना कमाई का खुलासा किया तो इंटरव्यू लेने वाला कंटेंट क्रिएटर भी हैरान रह गया. न्यूयॉर्क में काम करने वाले इस भारतीय की सालाना सैलरी करीब 2.5 लाख डॉलर यानी 2.1 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. यह वायरल वीडियो उद्यमी और कंटेंट क्रिएटर पियूष मूंगा ने शेयर किया है.

रातों-रात सिक्योरिटी गार्ड बना करोड़पति

UAE की लॉटरी ने बदल दी जिंदगी?

हर हफ्ते करीब 1100 रुपये खर्च कर दोस्तों के साथ लॉटरी टिकट खरीदने वाला सिक्योरिटी गार्ड रातों-रात करोड़पति बन गया. उसकी कहानी के साथ संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की लौटरी का पूरा सिस्टम भी सुर्खियों में है.

- नेपाल के शख्स का लगा जैकपॉट
- 70 करोड़ रुपये से अधिक मिलेंगे

अबू धाबी के रुवैस इंडस्ट्रियल एरिया में ईद-उल-अजहा की छुट्टी वाली रात 26 साल का नेपाली युवक तैयब खान अपनी नाइट शिफ्ट में तैनात थे. गेट पर आने-जाने वालों की जांच करना और सुरक्षा व्यवस्था संभालना उनकी रोजमर्रा की जिम्मेदारी थी. चार साल पहले बेहतर भविष्य की तलाश में नेपाल से UAE पहुंचे तैयब को अंदाजा भी नहीं था कि एक ईमेल उनकी जिंदगी बदल देगा.

ड्यूटी के दौरान उनके फोन पर एक ईमेल आया. पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई छोटा-मोटा इनाम मिला होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेल खोला, उनके होश उड़ गए. गल्फ न्यूज़ के मुताबिक, यूएई लॉटरी के लकी ड्रॉ में उनके ग्रुप ने Dh30 मिलियन (करीब 70 करोड़ रुपये से अधिक) का ग्रैंड जैकपॉट जीत लिया था.

तैयब यह रकम अकेले नहीं जीते. उन्होंने अपने चार नेपाली दोस्तों के साथ मिलकर 2024 से नियमित रूप से लॉटरी टिकट खरीदना शुरू किया था. पांचों दोस्तों ने अपने ग्रुप का नाम 'Future Millionaires' रखा था. हर हफ्ते सभी Dh50-50 (करीब 1,100 रुपये) जमा करते और एक टिकट खरीदते थे.

मेहनत, दोस्ती और किस्मत की कहानी

तैयब खान की कहानी सिर्फ एक लॉटरी जीतने की नहीं है. यह उन लाखों प्रवासी कामगारों की कहानी भी है, जो अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए घर से हजारों किलोमीटर दूर काम करते हैं. चार साल की मेहनत, दोस्तों का साथ और एक छोटे से सपने ने उनकी जिंदगी बदल दी. तैयब की जीत यह भी दिखाती है.

'गवर्नर' रिव्यू: आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि पर बनी दमदार कहानी, लेकिन क्या पर्दे पर छोड़ पाती है गहरा असर?

थिएटर से बाहर निकलते हुए एक अजीब सी कशमकश दिल में रह जाती है। जब आप ऐसी किसी फिल्म का टिकट खरीदते हैं, जो हमारे देश के इतिहास के एक बहुत बड़े और नाजुक हिस्से से जुड़ी हो तो उम्मीदें आसमान छू रही होती हैं। 'गवर्नर' भी एक ऐसी ही कहानी लेकर बड़े पर्दे पर आई है, जिसकी नीव बहुत मजबूत और दिलचस्प है। डायरेक्टर चिन्मय मांडलेकर और प्रोड्यूसर विपुल शाह ने एक ऐसी घटना को चुना है, जिसने आज के हिंदुस्तान की पूरी तकदीर को बदल कर रख दिया, लेकिन क्या यह फिल्म सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज बनकर रह गई या फिर एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव दे पाई? आइए इस पर तफ्सील से बात करते हैं।फिल्म की शुरुआत हमें सीधे उस दौर में ले जाती है जहां सब कुछ बहुत शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा तूफान पक रहा है। अमूमन ऐसी फिल्मों में पहले ही फ्रेम से सब कुछ साफ कर दिया जाता है, लेकिन 'गवर्नर' यहां थोड़ा सा अलग रास्ता चुनती है। शुरुआत में कहानी अपने पत्ते बहुत धीरे-धीरे खोलती है। यह किसी आम कमर्शियल फिल्म की तरह तेज तर्रार गानों या मारधाड़ से शुरू नहीं होती, बल्कि एक दफ्तर की खामोशी और फाइलों के बीच दबे उन राजों से होती है, जो पूरे देश की किस्मत तय करने वाले थे। फिल्म का माहौल आपको धीरे-धीरे अपनी तरफ खींचता है। यह देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे एक आम इंसान को अचानक एक ऐसी कुर्सी पर बिठा दिया जाता है, जहाँ से गिरने का मतलब सिर्फ उसका नुकसान नहीं, बल्कि पूरे देश का दिवालिया होना था। निर्देशक ने शुरुआत में ही यह साफ कर दिया कि यह फिल्म किसी एक हीरो की नहीं, बल्कि उस कुर्सी और उस पर बैठे इंसान की जिम्मेदारी की कहानी है। यह शुरुआती हिस्सा काफी सधा हुआ है और दर्शकों के मन में एक उत्सुकता जगाता है कि आगे क्या होने वाला है। फिल्म की मुख्य कहानी साल 1991 के उस दौर पर आधारित है जब भारत के पास अपना देश चलाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग खत्म होने की कगार पर था। कहानी के केंद्र में हैं ए. रमणन (मनोज बाजपेयी), जिन्हें अचानक देश के राष्ट्रीय बैंक (आरबीआई) का गवर्नर बना दिया जाता है। रमणन का कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए उनके खुद के डिप्टी गवर्नर सी रंगराजन (नौशाद मोहम्मद कुंजू) और सरकार के कई बड़े अधिकारी उन पर शक करते हैं। रमणन जब कार्यभार संभालते हैं तो उनके सामने गल्फ वॉर की वजह से पैदा हुआ एक भयानक संकट खड़ा होता है। देश के पास सिर्फ कुछ ही हफ्तों का पैसा बचा है। इसके बाद शुरू होती है समय के खिलाफ एक ऐसी दौड़, जहां रमणन को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से बात करनी है, विदेशों से कर्ज लेना है और जरूरत पड़ने पर देश का सोना तक गिरवी रखना है। पटकथा इस पूरे आर्थिक संकट को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करती है, ताकि एक आम दर्शक भी यह समझ सके कि आखिर उस वक्त देश किस दौर से गुजर रहा था। जब लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तभी रुपए की कीमत में भारी गिरावट आती है और कहानी में एक नया मोड़ आता है।

लखनऊ के बाद अमृतसर पहुंचेगा नीट विरोध आंदोलन अभिजीत दीपके का दौरा तय

अमृतसर में अभिजीत दीपके के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पंजाब में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी कार्यक्रम के स्वरूप और स्थान को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट के बाद समर्थकों में उत्साह दिखाई दे रहा है।

नीट पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ देशभर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (C J P) के संस्थापक अभिजीत दीपके अब पंजाब का रुख करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर करीब एक घंटे पहले साझा की गई एक पोस्ट के अनुसार अभिजीत दीपके 13 जून को शाम 4 बजे पंजाब के अमृतसर में मौजूद रहेंगे। इस घोषणा के बाद उनके समर्थकों और छात्र संगठनों के बीच नई चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि लखनऊ में हुए प्रदर्शन के बाद अब आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर और व्यापक बनाने की तैयारी की जा रही है। लखनऊके इको गार्डन में पेपर लीक के विरोध में आयोजित प्रदर्शन में अभिजीत दीपके दोपहर करीब 1:45 बजे पहुंचे। इससे पहले ही सोशल मीडिया पर उनके अगले कार्यक्रम की जानकारी साझा की जा चुकी थी। जारी पोस्ट के अनुसार अभिजीत दीपके 13 जून को पंजाबके अमृतसर में मौजूद रहेंगे। इस घोषणा के बाद उनके आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं, पंजाब के छात्रों और युवाओं के बीच भी उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। अभिजीत दीपके के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की गई पोस्ट में बताया गया है कि वह 13 जून को शाम 4 बजे अमृतसर पहुंचेंगे। पोस्ट सामने आने के कुछ ही समय बाद इसे बड़ी संख्या में लोगों ने साझा करना शुरू कर दिया। समर्थकों ने इसे छात्र आंदोलन के अगले चरण के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी की गतिविधियों का प्रमुख माध्यम बनकर उभरा है। पार्टी लगातार वीडियो, संदेश और पोस्ट के जरिए युवाओं से संवाद स्थापित कर रही है। ऐसे में अमृतसर कार्यक्रम की जानकारी भी सोशल मीडिया के जरिए ही सार्वजनिक की गई। लखनऊ में आयोजित प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों और युवाओं ने हिस्सा लिया था। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और कथित अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाना था। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। राजधानी लखनऊ के बाद अब अमृतसर में अभिजीत दीपके की मौजूदगी इस बात का संकेत मानी जा रही है कि संगठन विभिन्न राज्यों में जाकर युवाओं से सीधे संवाद स्थापित करना चाहता है। पार्टी का दावा है कि यह आंदोलन केवल किसी एक राज्य या परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि देशभर के छात्रों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों की चिंताओं से जुड़ा हुआ है। अभिजीत दीपके लगातार शिक्षा, रोजगार और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। लखनऊ में भी उन्होंने कहा था कि छात्रों के भविष्य से जुड़े सवालों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उनका कहना है कि यदि परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठते रहेंगे तो युवाओं का भरोसा व्यवस्था से कमजोर हो सकता है।इसी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी विभिन्न शहरों में जाकर छात्रों और युवाओं के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रही है। अमृतसर का कार्यक्रम भी इसी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है।

आधी रात को गत्ते में 7 दिन की मासूम मिली, राहगीर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र में कन्वेंशन सेंटर के पास आधी रात को गत्ते में 7 दिन की मासूम मिली है। बच्ची रो रही थी। रोने की आवाज सुनकर बच्ची के पास राहगीर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने डिब्बा खोला तो बच्ची कॉटन के बीच रखी गई थी। बच्ची को गुलाबी टॉप और डायपर पहनाया गया था। सूचना मिलते ही पीआरवी, गाजीपुर थाना पुलिस और सर्वोदय नगर चौकी की टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को अपनी सुरक्षा में लिया। पुलिस के अनुसार करीब 11:40 बजे पीआरवी को नवजात बच्ची मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद पुलिस टीम ने बच्ची को तत्काल अपने संरक्षण में लेकर उसकी स्वास्थ्य जांच कराई। प्राथमिक जांच में बच्ची स्वस्थ बताई जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि बच्ची को वहां छोड़कर जाने वाले व्यक्ति की पहचान की जा सके। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है और बच्ची की देखभाल के लिए संबंधित विभागों को भी सूचना दी गई है। पुलिस का कहना है कि नवजात को छोड़कर जाने वाले व्यक्ति की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दानपात्रों के चढ़ावे के गबन के मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दानपात्रों के चढ़ावे के पैसे और संपत्तियों के कथित गबन के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की गई है। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल की गई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से भी विशेष ऑडिट की मांग की गई है। इस मामले में अगले सप्ताह सोमवार या मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है। स्थानीय अधिवक्ता मोहित अशोक द्वारा व्यक्तिगत रूप से जनहित याचिका दाखिल की गई है। उन्होंने आवश्यक होने पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने का अनुरोध किया है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दानपात्रों में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित नकद धनराशि, सोने-चांदी के आभूषणों और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से विशेष ऑडिट कराया जाए।

याचिकाकर्ता का कहना है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र भगवान श्रीराम के मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन से संबंधित समाचार विभिन्न मीडिया माध्यमों में प्रकाशित हुए हैं, जिससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और वित्तीय लेखा परीक्षण जरूरी है। जनहित याचिका में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सीबीआई, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) तथा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले दान और बहुमूल्य वस्तुओं के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र एजेंसी से जांच और कैग से ऑडिट कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

LU में परीक्षा को लेकर विवाद निष्कासित छात्रों को रोका गया

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय में निष्कासित छात्रों को परीक्षा में शामिल होने से रोके जाने पर शुक्रवार को नया विवाद खड़ा हो गया। परीक्षा केंद्र पर पहुंचे निष्कासित छात्रों और प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। छात्र परीक्षा देने की मांग पर अड़े रहे, जबकि प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने परीक्षा नियंत्रक के आदेश का हवाला देते हुए उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। इस दौरान परीक्षा केंद्र के बाहर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। छात्रों का कहना था कि परीक्षा में शामिल होने का अवसर उनका शैक्षणिक अधिकार है, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन अनुशासनात्मक कार्रवाई के आधार पर उन्हें परीक्षा से वंचित कर रहा है। काफी देर तक चले विवाद के बाद छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिला। सभी छात्र पुनः अपने धरना स्थल पर पहुंच गए और आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। उधर, धरना स्थल पर छात्रों का समर्थन करने के लिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय पहुंचे। उन्होंने छात्रों से पूरे मामले की जानकारी ली और विश्वविद्यालय प्रशासन के फैसले को अन्यायपूर्ण बताते हुए आंदोलन को समर्थन देने की बात कही। बैनर के सामने छात्रों द्वारा हाथों में लिए गए पोस्टरों पर लिखा था "या तो निष्कासन वापस लो, या हमारी हत्या कर दो, हम छात्र हैं अपराधी नहीं।" इस संदेश के जरिए छात्रों ने अपनी नाराजगी और मानसिक पीड़ा को व्यक्त करने का प्रयास किया।

14 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (UPHC) को पॉलीक्लीनिक के रूप में अपग्रेड किया गया

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ के शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 14 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (UPHC) को पॉलीक्लीनिक के रूप में अपग्रेड किया गया है। इन पॉलीक्लीनिक का लोकार्पण शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। कार्यक्रम में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इन पॉलीक्लीनिक के शुरू होने से मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा अपने घर के नजदीक ही मिल सकेगी और उन्हें छोटी-बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए बड़े सरकारी अस्पतालों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। विभागीय योजना के मुताबिक सभी पॉलीक्लीनिक में आठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन, नेत्र रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ, ईएनटी सर्जन और मनोचिकित्सक शामिल हैं।

उन्नाव के एमआरएस इंटर कॉलेज में 3.01 करोड़ रुपये गबन

मामला पांच आरोपियों पर मुकदमा दर्ज

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव जिले में एमआरएस इंटर कॉलेज पुरवा में हुए 3.1 करोड़ रुपये गबन के मामले में डीएम घनश्याम मीणा के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने कॉलेज के लिपिक, विभागीय वरिष्ठ सहायक व दो परिचारकों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मामले में पहले ही आरोपियों को निलंबित किया जा चुका है। अब तक इन आरोपियों से 73 लाख की रिकवरी कराई जा चुकी है। यह लोग यह वित्तीय अनमीयता पिछले चार पांच सालों से करते चले आ रहे है। दरअसल, डेढ़ से दो महीने पहले कॉलेज के बाबू राधेश्याम ने शिकायत की थी कॉलेज वरिष्ठ बाबू अमित कुमार मिश्र ने अपने खाते के साथ उनके और परिचारक विनोद कुमार त्रिपाठी व कुलदीप कुमार के बैंक खातों में 30137109 रुपये अलग-अलग तारीखों में डलवाए गए थे। यह पूरा मामला तत्कालीन डीएम गौरांग राठी तक पहुंचा तो उन्होंने तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी थी। जांच टीम ने जो रिपोर्ट में डीएम को दी थी उसमें गबन की पुष्टि हुई थी। इस मामले जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय के बाबू सागर कपूर ने अधिकारियों के सामने गलत आंकड़े पेश किया था और उनके द्वारा डोंगल का गलत इस्तेमाल भी किया गया जिसके वजह से उनकी भी मिलीभगत पाई गई और उपरोक्त सभी को सस्पेंड कर दिया गया था । डीएम घनश्याम मीणा के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक सुनील दत्त ने सदर कोतवाली में अमित कुमार मिश्रा प्रधान लिपिक, विनोद कुमार त्रिपाठी परिचराक, कुलदीप कुमार परिचराक, राधेश्याम लिपिक और जिला विद्यालय निरीक्षक के वरिष्ठ सहायक सागर कपूर के ऊपर सरकारी धन गबन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया गया और इन आरोपियों से 73 लाख की रिकवरी कराई जा चुकी है। दरअसल, डेढ़ से दो महीने पहले कॉलेज के बाबू राधेश्याम ने शिकायत की थी कॉलेज वरिष्ठ बाबू अमित कुमार मिश्र ने अपने खाते के साथ उनके और परिचारक विनोद कुमार त्रिपाठी व कुलदीप कुमार के बैंक खातों में 30137109 रुपये अलग-अलग तारीखों में डलवाए गए थे। यह पूरा मामला तत्कालीन डीएम गौरांग राठी तक पहुंचा तो उन्होंने तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी थी। जांच टीम ने जो रिपोर्ट में डीएम को दी थी उसमें गबन की पुष्टि हुई थी। डीएम घनश्याम मीणा के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक सुनील दत्त ने सदर कोतवाली में अमित कुमार मिश्रा प्रधान लिपिक, विनोद कुमार त्रिपाठी परिचराक, कुलदीप कुमार परिचराक, राधेश्याम लिपिक और जिला विद्यालय निरीक्षक के वरिष्ठ सहायक सागर कपूर के ऊपर सरकारी धन गबन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया गया और इन आरोपियों से 73 लाख की रिकवरी कराई जा चुकी है।

साधु बाबा हत्याकांड में तीन आरोपी गिरफ्तार, दो की तलाश जारी

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के बांगरमऊ कस्बे के घूरे टोला मोहल्ले में साधु बाबा रामदास की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को हुई इस हत्या के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर गुरुवार दोपहर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

मृतक बाबा के भाई वीरेंद्र सिंह पुत्र रामबली सिंह निवासी घूरे टोला की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बिल्हौर मार्ग स्थित कल्याणी नदी के पास से मोहम्मद शफी (42 वर्ष, निवासी पूर्विया टोला), लल्ली उर्फ अजय (45 वर्ष, निवासी कस्बा मोहल्ला गुलाम मुस्तफा) और यामीन (36 वर्ष, निवासी पूर्विया टोला) को गिरफ्तार किया गया।

इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी इजराईल और उसके साथी शानू की तलाश में पुलिस और सर्विलांस टीम लगातार जुटी हुई है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं को लेकर गंभीरता से

. एक्सप्रेसवे पर सड़क पार कर रहे श्रमिक को वाहन ने रौंदा, मौत

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क पार करते समय तेज रफ्तार वाहन ने श्रमिक को कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। श्रमिक की मौत से साथी बेहोश हो गया। औरास थाना क्षेत्र के जमालनगर गांव निवासी रामचंद्र (60) गांव के ही शिवकुमार (55) और राजू (40) के साथ बहराइच स्थित पार्क में घास लगाने 10 दिन पहले गए थे। बृहस्पतिवार को तीनों लोडर में बैठकर एक्सप्रेसवे के रास्ते जमालनगर आए। लोडर से उतरने के बाद गांव जाने के लिए तीनों सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान आगरा की ओर से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने रामचंद्र को रौंद दिया। यह देखकर राजू वहीं बेहोश होकर गिर गया। गनीमत रही कि कोई वाहन नहीं आ रहा था। साथ रहे शिवकुमार ने चेहरे पर पानी के छींटे डाले तो होश में आया। मृतक की पत्नी अनारकली ने बताया पति घास लगाने का काम करते थे। दो बेटे हैं। दोनों की शादी हो चुकी है। थानाध्यक्ष संजीव कुशवाहा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। वाहन का पता लगाया जा रहा है।

गंगा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई

उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। यह घटना थाना आसीवन क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 387.6 के पास हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एक ट्रक में खराबी आने के कारण चालक ने उसे सड़क किनारे खड़ा कर दिया था। इसी दौरान पीछे से आ रही एक टाटा पंच कार ने उसमें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवार दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी मच गई। जिसके बाद राहगीरों और एक्सप्रेसवे कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना आसीवन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को उपचार के लिए सीएचसी मियागंज भेजा। जहां उनका इलाज जारी है। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया। उन्होंने दुर्घटना के कारणों की जांच की और मौके पर मौजूद लोगों से जानकारी जुटाई। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात व्यवस्था को सामान्य कराया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार की रफ्तार काफी अधिक थी, जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा बताई जा रही है। इसी तेज गति के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

कल्लूपुरवा नेशनल हाईवे पर चलते ट्रक में भीषण आग लग गई

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के गंगाघाट थाना क्षेत्र स्थित कल्लूपुरवा नेशनल हाईवे पर गुरुवार शाम एक चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। कानपुर से लखनऊ की ओर जा रही इस ट्रक में अचानक आग लगने से हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक कानपुर से लखनऊ की दिशा में जा रही थी। कल्लूपुरवा के पास पहुंचते ही ट्रक से धुआं निकलने लगा। इससे पहले कि चालक कुछ समझ पाता, आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास से गुजर रहे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही जाजमऊ चौकी प्रभारी विनोद सिंह अपनी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए हाईवे पर यातायात को रोक दिया, ताकि कोई जनहानि न हो और राहत एवं बचाव कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। पुलिसकर्मियों ने आसपास मौजूद लोगों को सुरक्षित दूरी पर हटाया। उधर, दमकल विभाग को सूचना मिलते ही कई गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना की गईं। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग की तीव्रता अधिक होने के कारण इसे बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस और दमकल विभाग की संयुक्त टीम आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी रही। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक आशंका शॉर्ट सर्किट या इंजन में तकनीकी खराबी की जताई जा रही है, जिसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ट्रक चालक और परिचालक समय रहते वाहन से बाहर निकलने में सफल रहे। हालांकि, ट्रक को भारी नुकसान पहुंचा है। गंगाघाट पुलिस ने बताया कि आग लगने की सूचना पर तत्काल कार्रवाई की गई। दमकल विभाग की सहायता से आग पर काबू पाया जा रहा है। पुलिस ने यह भी पुष्टि की कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है और आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी।

युवक का कमरे में फंदे से लटका मिला शव

सदर कोतवाली के रामपुरी मोहल्ले में किराये के कमरे में परिवार के साथ रह रहे युवक का शव फंदे से लटका मिला। पिता के अनुसार एक लड़की से वीडियो कॉल पर विवाद के बाद बेटे ने यह कदम उठाया है, लड़की ने फोन करके बताया तब घटना की जानकारी हुई। पिता ने पुलिस को बताया कि बेटा जीएसटी विभाग में कामर्शियल टैक्स अफसर (सीटीओ) था और इस समय वाराणसी में नियुक्त था। औरैया जिले के थाना बिधूना के गांव तिलकपुर सरमेड़ी के मूल निवासी सियाराम सिंह ने बताया कि बेटा राघवेंद्र प्रताप सिंह (35) उन्नाव सदर कोतवाली के मोहल्ला रामपुरी में रमेश तिवारी के घर में कई साल से किराये के कमरे में रह रहा था। बेटे का साल 2018 में जीएसटी में सीटीओ के पद पर चयन हुआ था। पिता के अनुसार वह सिविल लाइंस के जीआईसी में शिक्षक थे और वर्ष 2025 में सेवानिवृत्त हुए थे। बृहस्पतिवार सुबह बेटे से फोन करके पेट की बीमारी का इलाज कराने के लिए कहा था। बेटे ने 17 से 20 जून तक लखनऊ में रहने और वहीं अच्छे अस्पताल में दिखवाने की बात कही थी। वह जीएसटी के लखनऊ के विभूतिखंड कार्यालय भी जाता था। बृहस्पतिवार शाम करीब पांच बजे बेटे की परिचित दिल्ली में रहने वाली लड़की ने उन्हें फोन करके बताया कि राघवेंद्र से उसकी फोन पर कुछ कहासुनी हो गई और उन्होंने फंदा लगा लिया है। उन्होंने उन्नाव जीआरपी में तैनात परिचित सिपाही आदेश पटेल को फोन करके जानकारी दी। इस पर कोतवाली पुलिस को बताया गया लेकिन जब तक पुलिस पहुंची राघवेंद्र की मौत हो चुकी थी। पिता ने बताया कि 20 दिन पहले राघवेंद्र गांव आया था। तीन भाइयों में बड़ा होने से उसकी शादी की बातचीत भी चल रही थी। मां संगीता व अन्य परिजन बेहाल हैं। कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि जांच के दौरान कोई पहचान पत्र नहीं मिला है। शव पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया गया है। परिजन को सूचना दी गई है। उनके आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

15 जून से नोएडा-ग्रेटर नोएडा में दौड़ेंगी डबल डेकर ई-बसें

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पहली बार इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें डबल डेकर ई-बसें भी शामिल हैं।15 जून से शुरू होने वाली इस सेवा से नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और दैनिक यात्रियों को सस्ती, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा मिलेगी।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना को हरी झंडी दिखाते हुए इसे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया।

नोएडा के लोग भी अब डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसों में सफर का मजा ले पाएंगे। 15 जून से ये बसें संचालित होंगी। दरअसल, पहली बार नोएडा-ग्रेटर नोएडा में इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत हुई है। नोएडा अथॉरिटी और यूपी परिवहन निगम मिलकर इन बसों का संचालन करेंगे। अभी फिलहाल 100 इलेक्ट्रिक बसें और 10 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। बसें चलने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों को बहुत राहत मिली। नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और दैनिक यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। यह तोहफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को दिया गया है। अब ग्रेटर नोएडा के लोग एयरपोर्ट से सीधा कनेक्ट होंगे। इसके अलावा कलेक्ट्रेट तक भी यह सभी बसें चलेंगी। अभी फिलहाल 110 बस चलाई जाएंगी। इसके बाद इन बसों की संख्या 500 कर दी जाएगी। सभी सेक्टर और सोसाइटियों को भी इन सिटी बसों से जोड़ा जाएगा। इससे ऑटो और कैब पर लोगों की निर्भरता कम होगी। ये सभी बसें इलेक्ट्रिक हैं, जिससे कि किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होगा। इन बसों का किराया भी 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक रखा गया है। जानकारी के मुताबिक, बसों का न्यूनतम किराया 20 रुपये और अधिकतम किराया 50 रुपये होगा। बस पूरी तरह से एयर कंडीशनर (एसी) है और सुरक्षा की दृष्टि से बस में चार सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। नोएडा सेक्टर-90 बस डिपो से इन बसों का संचालन होगा। शुरुआत में ये बसें चार रूटों पर चलेंगी। बॉटनिकल गार्डन से ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सूरजपुर कलेक्ट्रेट और गाजियाबाद न्यू बस अड्डा रूट से होकर चलेंगी। अधिकारियों ने कहा कि मांग के आधार पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार गौतम बुद्ध नगर को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शहर के लोगों को इलेक्ट्रिक बेसों का तोहफा दिया। तीनों प्राधिकरण को फिलहाल 11-11 सिटी बस दी गई हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें दादरी विधायक तेजपाल नागर मौजूद रहे। विधायक ने सीएम योगी का आभार जताया और कहा कि इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप सोचो ना... कभी त्रेता युग में भगवान श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे। लेकिन इसके बाद कभी अयोध्या वासियों को वायु सेवा प्राप्त नहीं हो पाई होगी। हजारों वर्षों तक अयोध्या उपेक्षित थी। आजादी के बाद भी लगातार अपमानित थी। आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर के तैयार है और महर्षि वाल्मीकि को समर्पित एयरपोर्ट आज अयोध्या में संचालित हो रहा है। लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काशी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नोएडा जो जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।

पीयूष गोयल ने अखिलेश यादव के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले चंदे में हेराफेरी की बात कही गई थी। गोयल ने कहा कि जनता को विपक्ष के नेता की बातों पर भरोसा नहीं है। गोयल ने पत्रकारों से कहा कि अखिलेश यादव के ट्वीट को कोई गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने कहा कि जिस तरह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को विकास से दूर रखा, वहां अराजकता का माहौल बनाया और भेदभाव की राजनीति को बढ़ावा दिया... उसे देखते हुए जनता उन्हें एक बार फिर नकार देगी। उन्होंने आगे कहा कि सत्ताधारी गठबंधन अपने प्रशासनिक कामकाज के रिकॉर्ड के दम पर अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखेगा।यादव के सोशल मीडिया पर यह दावा करने के बाद कि भक्तों के चढ़ावे से करोड़ों रुपये गायब हो गए हैं, राजनीतिक विवाद और बढ़ गया। उन्होंने इन गड़बड़ियों को बेहद शर्मनाक और दुनिया भर के लाखों भक्तों की आस्था पर सीधा प्रहार बताया। यादव ने न्यायपालिका से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया और मंदिर प्रशासन की शुरुआती सफाई को नाकाफी 40-सेकंड का स्पष्टीकरण और महज जुबानी औपचारिकता करार दिया। उन्होंने ट्रस्टियों की पूरी बैठक बुलाने और सुरक्षा फुटेज के साथ नकद राशि की गिनती का मिलान करने की मांग की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने इस नैरेटिव का जवाब देने के लिए तेज़ी से कदम उठाए हैं। महंत दिनेन्द्र दास महाराज ने कहा कि ट्रस्ट के सभी वित्तीय फ़ैसलों और लेन-देन का बारीकी से रिकॉर्ड रखा जाता है, उन्हें सामूहिक रूप से संभाला जाता है और उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

राजनाथ सिंह के रिश्ते के भतीजे की इंदौर में मौत,रोड पर एक वाहन ने टक्कर मार दी

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के रिश्ते के भतीजे की इंदौर में मौत हो गई। उन्हें रोड पर एक वाहन ने टक्कर मार दी थी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह Rajnath Singh के रिश्ते के भाई प्रदीप सिंह के बेटे प्रभात सिंह की हादसे में मौत हो गई। उनके शव को दिल्ली भेज दिया गया है। वहां से प्रभात सिंह के पार्थिव शरीर को वाराणसी ले जाया जाएगा जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। खास बात यह है कि प्रभात सिंह अचानक अपनी गाड़ी से उतर गए थे। वे दोबारा कार में बैठने ही जा रहे थे कि तेज रफ्तार बस ने कार को टक्कर मार दी। महज 10 सेकंड के फासले ने एक युवा जिंदगी छीन ली। इंदौर-देवास रोड पर गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। शिप्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर्विस रोड पर तेज रफ्तार बस ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। कार सवार युवक प्रभात अपनी कार में बैठ रहे थे। जब वे कार के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से तेज रफ्तार आ रही बस ने कार में टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि महज 10 सेकंड के फासले से प्रभात भी दुर्घटना की चपेट में आ गए। अन्यथा जान बच सकती थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वे देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के रिश्ते में भतीजे थे। हादसे में उनके तीन दोस्त भी घायल हो गए। हादसे की खबर मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। राहगीरों और पुलिस की मदद से घायलों को तुरंत कार से बाहर निकाला गया। प्रारंभिक सूचना मिली की मृतक भाजपा से जुड़ा है, तो कई नेता घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। वहीं, सोनकच्छ विधायक राजेश सोनकर भी घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक प्रभात के शव को पोस्टमार्टम (पीएम) के लिए इंदौर के अरविंदो अस्पताल भिजवाया। यहां से पोस्टमार्टम के बाद शव दिल्ली भेज दिया गया है। वहां से शव बलिया उत्तर प्रदेश ले जाया जाएगा।

घायल बदमाश के खिलाफ दर्ज हैं कई मुकदमे

वाराणसी में शिवपुर थाना क्षेत्र के ऊंदी के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में पुलिस ने दो लोग गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक के पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक, जीएसटी अधिकारी के शिवपुरी स्थित ससुराल में आरोपियों ने करीब ढाई करोड़ की चोरी को अंजाम दिया था, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में शुक्रवार की सुबह पुलिस को यह कामयाबी हाथ लगी है। जानकारी के मुताबिक, एसओजी प्रभारी गौरव कुमार सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि शिवपुर थाना क्षेत्र के गणेशपुर इलाके में जीएसटी अधिकारी के ससुराल में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी ऊंदी के पास मौजूद हैं। इस सूचना के बाद एसओजी प्रभारी ने शिवपुर पुलिस की टीम के साथ मिलकर मौके पर घेराबंदी की। इस दौरान एक बाइक पर सवार होकर दो लोग आते दिखे, जिन्हे पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस ने बताया कि इस दौरान बदमाशों ने बाइक तेज कर दी और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। वहीं, पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में विशाल नामक बदमाश को पैर में गोली लग गई। इसके बाद वह नीचे गिर पड़ा। वहीं, उसका साथी रोहित पुलिस से बचने के लिए भागने लगा। इसके बाद एसओजी के जवानों ने उसे दौड़ा कर पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ की इस घटना में घायल हुए बदमाश विशाल के खिलाफ वाराणसी के विभिन्न थानों में एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल, मूल रूप से बिहार के सासाराम जनपद के रहने वाले विनोद कुमार का शिवपुर में मकान है। बीते 1 जून को पूरा परिवार चाचा की तेरही में शामिल होने के लिए बिहार गया हुआ था। इसी दौरान उनके घर में रखें 1.90 लाख रुपए कैश, हीरे, सोने व चांदी के आभूषण चोरी हो गए थे।